फार्म फॉरवर्ड

वर्ष-1, अंक-1 8 सितम्बर 2024

जायका कृषि परियोजना-2 की मासिक ई-पत्रिका

Farm Forward

MONTHLY E-PAPER OF HPCDP (PHASE-II), JICA-ODA

उत्कृष्टता केंद्र, बड़ा-नादौन में तैयार पौध का वितरण शुरू

मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह ने किया उद्घाटन • किसानों व कृषि छात्रों के लिए वरदान • 70 हजार 900 गोभी जातीय पौधों की मांग

हमीरपुर, बड़ा (नादौन) उत्कृष्टता केंद्र बड़ा में तैयार गोभी प्रजाति की पौध का वितरण शनिवार 28 सितम्बर से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना-2 द्वारा स्थापित इस पौध उत्कृष्टता केंद्र का अगस्त में उद्घाटन किया था।

मुख्यमंत्री ने इस पौध उत्कृष्टता केंद्र किसानों को समर्पित करके उन्हें एक बड़ी सौगात दी, जिसके परिणाम यहां उगाई गई गोभी प्रजाति की नर्सरी के वितरण के साथ सामने आ गए हैं। जायका कृषि परियोजना-2 ने यह उत्कृष्टता केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में लगभग एक करोड़ रूपये की लागत से बनाया है।

इस केंद्र से किसानों को हर मौसम में सब्जियों की रोगरहित और स्वस्थ पौध मिलने लगी है।

इस मौसम में अब फूलगोभी, पत्तागोभी और

ब्रोकली की पौध तैयार हो चुकी है। किसानों ने इस केंद्र से उच्च गुणवत्ता वाली पौध खरीदना शुरू कर दिया है। गोभी प्रजाति की पौध की रोपाई इन दिनों की जा रही है।

हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी परियोजना जिलों की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के किसानों ने अपने-अपने जिलों से इस केंद्र को फूलगोभी के 29 हजार 900, पत्तागोभी के 21 हजार और ब्रोकली के 10 हजार पौधों की मांग भेजी है। यह केंद्र अब 70 हजार 900 पौध जल्द ही किसानों तक पहुंचा देगा।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना ने किसानों को इस केंद्र में उगाई जाने वाली पौध की विशेषताओं और उनके लाभों के बारे में हर किसान शिविर में जागरूक करने का प्रयास किया है। इस केंद्र में तैयार की गई पौध स्वस्थ होती है और मिट्टी जनित बीमारियों से मुक्त होती है। इसके अलावा, यहां की पौध रोपाई के बाद खेत में जल्दी जड़ पकड़ लेती है। स्वस्थ और मजबूत होने के कारण इस रोपित पौध की फसल में बीमारियां और कीट भी कम लगते हैं। इस कारण से फसल उत्पादन की लागत भी कम रहती है और किसान की आमदनी में बढ़ौतरी होती है।

पौध उत्कृष्टता केंद्र, बड़ा (नादौन) प्रदेश के कृषि एवं वानिकी महाविद्यालयों को भी समर्थन दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला केंद्र है जिसमें सभी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नर्सरी उत्पादन के लिए किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी के छात्रों ने इस केंद्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने उन्नत नर्सरी तकनीकों का अध्ययन किया और पौध उत्पादन प्रक्रिया को नजदीक से देखा। यह अनुभव उनके भविष्य के कृषि कार्यों में मददगार साबित होगा।

अब जो भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करने जा रहा है वह उत्कृष्टता केंद्र से फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रोकली सब्जियों की नर्सरी खरीदने लगा है।

इस पौध उत्कृष्टता केंद्र में पहला बैच फूलगोभी की 40 हजार, पत्तागोभी की 30 हजार और ब्रोकली की 10 हजार पौध को उगाया।

पौध उत्कृष्टता केंद्र बड़ा से तैयार नर्सरी का वितरण 28 सितम्बर को बड़ा और नादौन क्षेत्र के किसानों को किया गया है। उस दिन फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रोकली की 8 हजार पौध की आपूर्ति की गई। शेष पौधों की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के सभी खंडों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी कर दी गई है, ताकि किसान जल्द से जल्द अपने खेतों में पौध का रोपण कर सकें। स्थानीय सब्जी उत्पादकों सुनील कुमार, संतोष चौहान, मनवीर, नवनीत और मुरारी लाल (गांव हार, रैल) का कहना है कि बड़ा पौध केंद्र से उन्हें बड़ी राहत मिली है, और अब वे यहां से पहले ही बुकिंग कर पौध प्राप्त करेंगे। यदि किसी किसान को पौध की आवश्यकता हो, तो वे जिला परियोजना प्रबंधक, हमीरपुर, 01972-292155 या खंड परियोजना प्रबंधक, हमीरपुर से 01972-299885 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

स्वस्थ पौध से अधिक लाभ उठाएं किसानः डा. चौहान

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के परियोजना निदेशक, डॉ. सुनील चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे इस उत्कृष्टता केंद्र से स्वस्थ पौध खरीद कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं और नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बड़ा के केंद्र में तैयार की गई पौध का उपयोग किसानों के लिए समय और खर्च दोनों में बचत करेगा और वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस केंद्र में परियोजना क्षेत्र के किसानों की मांग पूरी होने के बाद थोड़ी पौध बच जाएगी जिसे हमीरपुर या इसके आस-पास के किसान कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ा या जिला परियोजना प्रबंधक इकाई हमीरपुर में अपनी मांग दर्ज करवा कर पौध खरीद सकते हैं। किसानों को यहां की पौध केवल दो रुपये प्रति पौधे की दर मिल रही है। डॉ. चौहान ने बताया कि इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना की ओर से कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के साथ एमओयू किया गया है। केंद्र को परियोजना और कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर मिलकर संचालित करेंगे तथा परियोजना की अवधि पूरी होने के बाद कृषि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

परियोजना निदेशक की अपील

संदेश

प्रो. चौधरी चंद्र कुमार
कृषि मंत्री, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 विभिन्न नवीन कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से इस पहाड़ी राज्य के किसानों के उत्थान में कार्यरत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में सरकार की किसानों के लिए प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी का प्रचार और प्रसार करने के लिए विस्तार परियोजना का एक आवश्यक और एकीकृत घटक है। मुझे बताया गया है कि जायका परियोजना अक्तूबर 2024 में कृषक परिवारों के लिए 'फार्म फॉरवर्ड' नाम से एक हिंदी मासिक ई-पेपर निकाल रही है। मैं परियोजना समर्थन मीडिया के प्रयासों में हिंदी मासिक ई-पेपर के शुभारंभ के लिए हिमाचल परियोजना प्रबंधन और इसकी सूचना शिक्षा और संचार टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

संदेश

डॉ. सी पौलरसु (आईएएस)
कृषि सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार

मैं हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 की मासिक हिंदी ई-पत्रिका 'फार्म फॉरवर्ड' के शुभारंभ पर एचपीसीडीपी-2 की पूरी टीम और उनकी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) इकाई को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह ई-पत्रिका न केवल परियोजना की गतिविधियों को जनता और किसानों तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा, बल्कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण नवाचारों, उपलब्धियों और सफलताओं को भी उजागर करेगा। फसल विविधीकरण, किसानों की आय में वृद्धि और हिमाचल प्रदेश की कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे यह सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ई-पत्रिका सभी हितधारकों के बीच संचार को सुदृढ़ करेगा और परियोजना की पारदर्शिता और प्रगति को गति प्रदान करेगा। यह ई-पत्रिका किसानों के लिए जानकारी का एक समृद्ध स्रोत बनेगा और कृषि के क्षेत्र में नई दिशा और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संदेश

डॉ. सुनील चौहान
परियोजना निदेशक

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान द्वारा आईईसी टीम को अपना ई-पेपर बनाने पर बधाई देते हुए कहा कि हम सभी का दायित्व बनता है कि परियोजना में चल रही विभिन्न गतिविधियों को कैसे लाभान्वित किसानों तक पहुंचाये जा सकें इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि वह इन योजनाओं से लाभ ले सकें। इसके लिए आईईसी टीम का ये छोटा सा प्रयास सराहनीय है।

मैं आशा करता हूँ कि इस ई पेपर में जो जानकारियां होंगी वो प्रदेश के किसानों को तो लाभान्वित करेगी इसके साथ हमारे सभी उप परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन इंवार्ज और एक्सटेंशन इंवार्ज को भी लाभान्वित करेगी उनके कार्य करने की कार्य पद्धति में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

जापान की जायका टीम नई कृषि पद्धतियों का जायजा लेने 8 अक्तूबर को आएगी हिमाचल

हमीरपुर। जायका मुख्यालय मिशन का एक प्रतिनिधि मंडल 8 अक्तूबर को नई कृषि पद्धतियों की जानकारी लेने हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 का दौरा करेगी। जायका मिशन की टीम का उद्देश्य लाभार्थी किसानों से मिलकर उनकी प्रतिक्रियाएं लेना और फसल विविधीकरण के तहत अपनाई जाने वाली नई कृषि पद्धतियों के परिणामों की जानकारी लेगी। यह टीम जायका कृषि परियोजना-2 के दौरान चल रही विभिन्न गतिविधियों में हो रही प्रगति और स्थिति और इनकी सफलता का भी आंकलन करेगी। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा जिला परियोजना प्रबंधक इकाई पालमपुर में कई उप-परियोजनाओं को देखेंगे। जायका प्रतिनिधि मंडल पालमपुर के पपरोला में संग्रह केंद्र का भी दौरा करेगा, जहां वह किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ) बैजनाथ प्रगतिशील किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के पदाधिकारियों और किसानों के साथ बातचीत करेगा। यह टीम जायका कृषि परियोजना चरण-1 में बने बिक्री केंद्र, पपरोला का दौरा भी करेगी। जापान की इस टीम के सदस्य पालमपुर में बने शिटाके खेती और प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करेंगे जहां वह शिटाके खुम्ब उत्पादकों और प्रसारकों के साथ बातचीत करेंगे। टीम के सदस्य जायका कृषि परियोजना चरण-2 में बन रही सिंचाई उप-परियोजना संध कुहल के क्षेत्र में जाएगी। उप-परियोजना संध कुहल, धर्मशाला खण्ड परियोजना इकाई के अंतर्गत आती है। यहां यह टीम कृषक विकास संघ के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी और सिंचाई के बुनियादी ढांचे पर चर्चा करेगी। टीम के सदस्य भट्ठ के कलेक्शन सेंटर और भवारना की फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ, के पदाधिकारियों व किसान सदस्यों से बातचीत करेगी।

जायका इंडिया से परियोजना चित्रों पर मिला पुरस्कार

हमीरपुर। भारत में चल रही जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से वित्तपोषित सभी परियोजनाओं में फोटो प्रतियोगिता (2024-25) करवाई। यह प्रतियोगिता परियोजनाओं में चल रही विभिन्न गतिविधियों की सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों के लिए आयोजित करवाई गई थी। उन तस्वीरों को 2 सितंबर, 2024, नई दिल्ली में आयोजित सेमिनार की फोटो गैलरी में भी प्रदर्शित किया जाना था। इसी सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-2) ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। परियोजना द्वारा विभिन्न गतिविधियों की 25 फोटो जायका इंडिया प्रतियोगिता के लिए भेजे, ये फोटो खंड परियोजना प्रबंधक के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उप-

परियोजनाओं में चल रही प्रचार-प्रसार के कार्यों, निर्माण कार्यों और शिटाके खेती एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पालमपुर में चल रही विभिन्न गतिविधियों की थी।

यह हर्ष का विषय है कि परियोजना द्वारा भेजी फोटो में से 11 फोटो जायका इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ घोषित करके, नई दिल्ली में आयोजित सेमिनार की फोटो गैलरी में भी प्रदर्शित किया और साथ ही हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-2) को "सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड" से भी नवाजा। इसका पूरा श्रेय परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधक इकाई, हमीरपुर की आईईसी टीम, सभी जिला परियोजना प्रबंधक इकाइयां, सभी खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाइयों के साथ-साथ शिटाके खेती प्रशिक्षण केंद्र, पालनपुर के समर्पित अधिकारियों/कर्मचारियों को जाता है। आपका समर्पण हम सभी को उत्कृष्टता और नवाचार के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है और आगे भी करता रहेगा। परियोजना उपरोक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से आगामी किसी भी प्रतियोगिता में उत्साहपूर्ण भाग लेने की आशा रखती है।

जायका व शिवा प्रोजेक्टों में आपसी सहयोग पर हुई सांझी बैठक

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 और शिवा परियोजना के बीच पोस्ट -हार्वेस्ट विषय में आपसी सहयोग करेंगे। इस आशय पर शनिवार को यहां जायका परियोजना के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान और शिवा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. डीएस ठाकुर के बीच बैठक हुई। दोनों परियोजना के अधिकारीयों ने पोस्ट हार्वेस्ट संसाधनों के सांझे उपयोग पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई। इसे किसानों के हित में सिरे चढ़ाने के लिए आगे की कार्यवाही करने के लिए कार्यक्रम तय किया। डॉ. सुनील चौहान ने बताया की जायका परियोजना-1 में बने कुछ संग्रहण केंद्रों पर बने संसाधनों का उपयोग शिवा प्रोजेक्ट कर सकता है ताकि किसानों को दोनों प्रोजेक्टों की सुविधाएं और केंद्र की उपयोगिता का लाभ मिल सके। इसकी सहमति देते हुए डॉ. डीएस ठाकुर ने कहा कि जायका परियोजना -2 और शिवा प्रोजेक्ट दोनों मिलकर कुछ सग्रहण केंद्रों के लिए कृषि व उद्यान विभागों से मदद लेकर विभिन्न स्तरों पर गठित किसानों के संगठनों से समन्वय बिठाकर पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

बैठक में प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें कांगड़ा के बागवानी उप निदेशक डॉ. केएस नेगी, हमीरपुर के बागवानी उप निदेशक डॉ. आर परमार, शिवा प्रोजेक्ट के सहायक परियोजना अधिकारी डॉ. नौत अंगारिया शामिल हुए।

''फसल विविधीकरण से कृषि उपज को बढ़ाना है, कृषि के क्षेत्र में प्रदेश का नाम और ऊंचा उठाना है''

7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 एक स्वस्थ भारत की ओर एक कदम

हमीरपुर। सितंबर, 2024 में पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत वार्षिक अभियान के रूप में मनाया जाता है। यह कुपोषण को संबोधित करने और बेहतर पोषण और स्वास्थ्य आचरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वार्षिक अभियान है। यह पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, आहार आचरण में सुधार करने और बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं सहित कमजोर समूहों के बीच कुपोषण का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान के तहत हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। यह संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप कार्यक्रम है। पोषण माह के दौरान पूरे देश में कई

कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जैसे पौध रोपण अभियान, पोषण सप्लीमेंट्स का वितरण, समुदाय आउटरीच प्रोग्राम, प्रदर्शनी और शैक्षणिक सत्र। इनके माध्यम से लोगों को पोषण और जीवनशैली चुनौतियों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के प्रमुख विषय एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक भोजन, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम।

पोषण अभियान क्या है?

यह अभियान मार्च, 2018 से किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 साल तक के बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कमजोरी, कम पोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

पोषण अभियान के घटक

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस यह लक्ष्य-निर्धारण, क्षेत्र की बैठकों और विकेंद्रीकृत योजना के माध्यम से समन्वय को बढ़ावा देता है।

कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

यह सॉफ्टवेयर पोषण की स्थिति को ट्रैक करने और विकास निगरानी उपकरणों को नियोजित करता है।

पोषण ट्रैकर क्या है?

यह एक मोबाइल ऐप है जो भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ट्रैक और मॉनिटर करता है। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो उनके हस्तक्षेप की प्रगति और प्रभाव को दर्शाता है और वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है। यह एक इंटरैक्टिव टूल है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का उपयोग करके बच्चे के विकास को मापता है और इनपुट के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव प्रदान करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 6 प्रकार के लाभार्थियों को पंजीकृत कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 0-6 महीने के बीच के बच्चे, 6 महीने से 3 साल के बच्चे, 3-6 साल के बच्चे और 14-18 वर्ष की आयु की किशोरियां (विशेष रूप से आकांक्षी जिलों के लिए)।

पोषण के लिए परियोजना द्वारा उठाये गये कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2, इस पोषण अभियान के लिए दृढ़ संकल्प होकर अग्रसर हैं। इस पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए उप परियोजना में लगने वाले एक दिवसीय शिविरों में इस अभियान की चर्चा और उसके निवारण के लिए किसानों को मोटे आनाज उगाने के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। इसके साथ किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपनी फसल में कम से कम जहर का प्रयोग करें और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा

चलाई प्राकृतिक खेती योजना के साथ ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ें ताकि सेहत, जमीन और गांव का वातावरण सुरक्षित रहे, उस अनाज को खाने वाला भी सेहतमंद रहे इसके लिए इस वर्ष परियोजना की तरफ से 517 बीघा भूमि में फिंगर मिल्लेट्स की खेती अपने विभिन्न उप परियोजना के किसानों से करवा रहे हैं। ताकि जब उस आनाज को गांव में रहने वाले बच्चे, माताएं व बजुर्ग खाएं तो उनकी सेहत ठीक रहे उनको कम से कम बिमारियों का सामना करना पड़े।

जापानी कंपनी का परियोजना क्षेत्र में खेती सेवा प्रस्ताव

परियोजना और कंपनी के प्रबंधन अधिकारियों की बैठक

हमीरपुर। जापान की एक कंपनी एम2लैबो और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के हितधारकों के बीच एक विकसित मॉडल फार्म योजनाओं को परियोजना क्षेत्र में लागू करने पर विचार बैठक हुई। जायका इंडिया की प्रतिनिधि इनागाकी युकारी ने इस बैठक की अध्यक्षता, परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान की मौजूदगी में की। इसमें जायका इंडिया की विकास विशेषज्ञ वेंगुलेंकर निष्ठा के अलावा परियोजना के अधिकारियों ने भी भाग लिया। चर्चा का मुख्य विषय कंपनी की ओर से जैसी उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करके एक मॉडल फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। इन तकनीकों में निंजा टनल और मोबाइल मूवर के प्रयोग भी शामिल हैं। इन तकनीकों को अपनाने का उद्देश्य सेब और स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों की खेती को बढ़ाना है, जिससे अधिक उपज और कम लागत सुनिश्चित हो सके। एम2लैबो की भारत इकाई के मुख्य विपणन अधिकारी श्री प्रसून अग्रवाल

ने कंपनी की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी दी। कंपनी ने सुजुकी कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मोबाइल मूवर विकसित किया है, जो एक बहुमुखी रोबोटिक मोबिलिटी उपकरण है। यह उपकरण सभी प्रकार के छिड़काव व निराई करने में सक्षम है। इस नई तकनीक से सेब के बागीचों में एकसार छिड़काव करके खरपतवार आदि को नष्ट करने में आशा जनक परिणाम दिखाये हैं। निंजा टनल, मॉडल फार्म योजना का एक और महत्वपूर्ण घटक है, जो ठंडे मौसम के दौरान ऊर्जा-कुशल खेती के लिए डिजाइन की गई एक किफायती विनाइल हाउस संरचना है। एम2लैबो जापान ने इस तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक लीक और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की खेती की है। बैठक में खेती की तकनीकों के अलावा, वेजि-बस पर भी प्रकाश डाला गया, जो सब्जियां और फल जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अभिधीतन वेजि-बस वितरण प्रणाली साबित हुई है। ई-कॉमर्स को लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के साथ मिलाकर, वेजि-बस का उद्देश्य खाद्य आपूर्ति वितरण प्रणाली को श्रृंखला बद्ध करना है, जिस से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की कुशल वितरण सुनिश्चित हो सके और जल्दी गलने-सड़ने वाली सब्जियां और फल सुरक्षित मॉडियों में पहुंच सकें। बैठक को इस निष्कर्ष पर समाप्त करते हुए डॉ. सुनील चौहान परियोजना निदेशक ने कहा कि जापान और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के बीच सहयोग के अवसरों में एम2लैबो की भूमिका की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से विभिन्न उप परियोजनाओं के किसानों की कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाना रहेगा।

क्यारी में नर्सरी कैसे तैयार करें

(क) बैड/क्यारी में नर्सरी/ पौध तैयार करने की विधि

उपयोग की जाने वाली सामग्री : मिट्टी : रेत : केंचुआ खाद /वर्मी कम्पोस्ट (2:1:1), बीज (किसी भी सब्जी के), छलनी, सींचने का कनस्तर/फव्वारा

(ख) बैड/क्यारी बनाने की विधि

1. तीन मीटर लम्बी, एक मीटर चौड़ी तथा 15-20 सैं.मी. ऊँची उठी हुई क्यारी तैयार करें।

सुझाव : बुवाई से 20-30 दिन पहले मिट्टी का सौरीकरण किया जा सकता है ताकि मिट्टी जनित बीमारियों, कीटों-खरपतवारों से बचा जा सके। सौरीकरण प्रक्रिया में नर्सरी बेड को प्लास्टिक की शीट से ढक दिया जाता है तथा सूर्य की रोशनी से उत्पन गर्मी से बीमारियों के कीटाणु व कीड़ों के अण्डे मर जाते हैं।

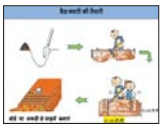

2. सीधी क्यारी बनाने के लिए, एक कोने से दूसरे कोने तक एक धागा फैलाएं और उसके अनुसार क्यारी बनाएं।

3. बोर्ड या लकड़ी की सहायता से 5-7 सैं.मी. के अंतर पर छोटी-2 नालियां /पंक्तियां बनाएं 7 नालियों की गहराई, सब्जिओं के बीज के प्रकार पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर गहराई, बीज के व्यास से तीन गुणा अधिक होनी चाहिए।

सुझावः नालियों की गहराई, सब्जिओं के बीज के प्रकार पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर गहराई, बीज के व्यास से तीन गुणा अधिक होनी चाहिए।

(ग) बैड/क्यारी में बीजाई

1. बीजों को लगभग 1 -1 सैं.मी. की दूरी पर बोएं।

2. बीजों को ढकने की लिए छनी हुई बारीक मिट्टी/रेत/वर्मी कम्पोस्ट डालें।

सुझाव : महीन मिट्टी और रेत से बीज के अंकुरण में आसानी होगी। नमी के संरक्षण हेतु मिट्टी की सतह को गेहूं के भूसे या सूखी घास से ढकें और बैड में उचित नमी बनाए रखने के लिए पानी के फव्वारे के साथ पानी डालें।

सावधानी : बैड को ढकने के लिए बीज तथा कीड़े रहित घास का प्रयोग करें।

(घ) पौध का संरक्षण

1. गर्मियों में क्यारी के ऊपर छाया की व्यवस्था करें ताकि, बैड के तापमान को कम किया जा सके।

सुझाव :

1. सर्दियों में तापमान बनाए रखने के लिए पॉलीहाउस/पॉलीटनल को प्रयोग में लाएं।

2. बीज के अंकुरण होते ही, सूखी घास को हटा लें।

सावधानी : जैसे ही अंकुरण दिखाई दें सूखी घास को बिना देरी किए हुए उसी समय हटा दें, ऐसा न करने पर तना दुबला-लंबा और पौध कमजोर होती है।

3. बीमारियों से बचाव के लिए अंकुरण के 4-5 दिन के बाद एहतियात के तौर पर डाईथेन एम-45 (2.5 ग्रा.) और बैविस्टिन (1 ग्रा.) प्रति लीटर पानी में घोलकर बैड की फव्वारे से सिंचाई करें।

(ङ) विरलीकरण और रोपाई

छंटाई :- 1. बैड/क्यारी में

घने उगे पौधों की छंटाई

सुझाव : विरलीकरण द्वारा पौध का आपस में प्रतिस्पर्धा को कम और बढ़वार की दर बढ़ाएगी।

2. छंटाई किये गए पौधों का उपयोग फिर से रोपने के लिए किया जा सकता है।

रोपाई की विधि

1. जब पौध 12-15 सैं.मी. की ऊंचाई प्राप्त कर लें तो 2-3 पत्तों वाली अवस्था आने पर इनकी रोपाई करें ।

2. रोपाई से पहले, 10 सैं.मी. से ज्यादा लंबी जड़ों को काट लें इससे नई जड़ों के अंकुरण में मदद मिलती है।

3. खेत में क्यारी बना लें तथा क्यारे में छोटे-छोटे छेद करके और उनमें उर्वरक की प्रारम्भिक मात्रा डाल दें और शाम के समय पौध को फसल की किस्म के अनुसार उचित दूरी पर रोपाई करें।

(च) पौध को सहनशील बनाना

1. पौध को पॉलीहाउस/पॉलीटनल से उखाड़ने और रोपाई से कम से कम 7-10 दिन पहले कुछ कृत्रिम झटके दिए जाते हैं - जैसे कि सूरज

की रोशनी और ठंडक के संपर्क में लाना, सभी छायादार जाली या प्लास्टिक शीट को हटाना, पौधों की वृद्धि को धीमा करने के लिए पानी देना कम करें, लेकिन पौधों को मुरझाने न दें। इससे पौध, प्रतिकूल मौसम जैसे गर्म दिन की हवाओं या कम या ज्यादा तापमान का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। अगर पौध पॉलीहाउस/पॉलीटनल में तैयार की गई है तो पौध को रोपाई से दिन पहले बाहरी वातावरण में रखें इससे पौध बाहरी वातावरण में ढल जायेगी।

''फसल विविधीकरण से कृषि उपज को बढ़ाना है, कृषि के क्षेत्र में प्रदेश का नाम और ऊंचा उठाना है''

डोहग सिंचाई योजना से 26 किसान परिवार होंगे लाभान्वित

किसानों को सौंपी उप-परियोजना डोहग

12.73 हेक्टेयर जमीन पर होगी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध

फसलों को उपलब्ध होगा बेहतर पानी

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अधिकारी डोहग प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को जागरुक करते हुए

हमीरपुर। 9 सितंबर 2024 को, उप-परियोजना डोहग में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, हमीरपुर और पीएमसी के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने उप-परियोजना में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। डॉ. हेमराज वर्मा ने इस सत्र की शुरुआत की। डॉ. राजेश कुमार (उप परियोजना निदेशक, एमपीएच) ने मशरूम उत्पादन और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन (एफपीओ) के गठन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि एफपीओ के गठन से किसानों को संगठित होकर बाजार तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी और वह सामूहिक रूप से उत्पादन और विपणन का प्रबंधन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने परियोजना द्वारा आयोजित गतिविधियों जैसे पीएमवीआरपी, जायका वेजिटेबल गार्डन और शेप की चर्चा की, जो उपरोक्त कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि की स्थिरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

डॉ. करतार सिंह, उप परियोजना निदेशक (एसडब्ल्यूसी), ने सिंचाई कुहलों के निर्माण और रख-रखाव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को कुहलों की देखभाल में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अब इस योजना को पूरी से तैयार कर दिया गया है और कृषक विकास संघ को सौंप दी गई है। केवीए के सदस्य अब बाड़बंदी प्रणाली तैयार करें, जिसके तहत यह तय किया जाएगा कि किस किसान को कब और कितना पानी मिलेगा। इसके साथ ही, वह पानी की दरें (टैरिफ) भी निर्धारित करेंगे ताकि सिंचाई जल का उपयोग सही तरीके से किया जा सके। डॉ. करतार सिंह ने यह भी बताया कि केवीए को जल वितरण की पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाना होगा और योजना के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी होगी ताकि यह योजना लंबे समय तक सफलतापूर्वक चल सके और सभी किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

डॉ. दुर्गा दत्त शर्मा, (उप परियोजना निदेशक ए एंड ई), ने फसल विविधता और बाजार की मांग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसानों को बाजार की प्रवृत्तियों और उपभोक्ता प्राथमिकताओं से अवगत रहना चाहिए ताकि वह बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन कर सकें। फसल विविधता को बढ़ावा देने से मिट्टी की सेहत बनी रहती है और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। विभिन्न फसलें मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकती हैं, कीट और रोगों के जोखिम को कम कर सकती हैं, और कुल मिलाकर कृषि की स्थिरता को बढ़ा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने मशरूम उत्पादन की चर्चा की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन (एफपीओ) बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिससे किसानों को संगठित होकर बाजार तक सीधी पहुंच मिल सके और वह सामूहिक रूप से उत्पादन एवं विपणन का प्रबंधन कर सकें। यह न केवल आर्थिक लाभ को बढ़ाएगा, बल्कि कृषि की स्थिरता और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा देगा।

डोहग सिंचाई योजना एक नजर में

उप-परियोजना डोहग को हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत प्रवाह सिंचाई योजना के विकास के लिए चुना गया है।

इस योजना के तहत किसानों को 12.73 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे फसलों को बेहतर पानी उपलब्ध होगा और पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

यह योजना कुल 26 किसानों की मदद करेगी। रुपए 37.27 लाख की लागत से इस प्रवाह सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है, और यह 100 प्रतिशत पूर्ण कर ली गई है।

योजना को पूरी तरह से तैयार करके 09 दिसम्बर 2021 को गठित किए गए केवीए को 10 जुलाई 2024 को संचालन और रखरखाव के लिए सौंप दिया गया है, ताकि योजना का सुचारू संचालन और रखरखाव हो सके।

मण्डी में 2520 किसानों को मिला प्रशिक्षण

हमीरपुर। जिला परियोजना प्रबन्धक इकाई, मण्डी क्षेत्र में सितंबर 2024 के दौरान 12 उप-परियोजनाओं की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही तीन नई उप-परियोजनाओं की विकास योजनाएं तैयार कीं। इस महीने चारों खण्ड परियोजना इकाइयों-कुल्लू, मण्डी गोहर और सरकाघाट में किसानों के लिए विभिन्न विषयों पर 72 प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिनमें फार्म प्रबंधन एवं बुक कीपिंग, अभिविन्यास एवं आवश्यकता मूल्यांकन, उद्देश्य एवं मानदंड, बुनियादी इंजीनियरिंग कौशल, सिंचाई एवं जल प्रबंधन आदि विषय शमिल थे। इनमें कुल 2520 किसानों ने भाग लिया। साथ ही विभिन्न उप-परियोजनाओं में 8 नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। इन मंचनों द्वारा किसानों को उप परियोजनाओं में चल रही गतिविधियों / योजनाओं से अवगत करवाया ताकि किसान इन योजनाओं का भरपूर फायदा ले सकें। विभिन्न उप-परियोजनाओं में 4 बेसलाइन सर्वेक्षण किए गए। खण्ड परियोजना प्रबन्धक इकाई, सरकाघाट ने सितंबर में दो उप-परियोजनाओं को पूरा किया। इनमें कुल 23.70 का हेक्टेयर कमांद क्षेत्र शामिल है। डोहग की बहाव सिंचाई योजना के तहत 12 अगस्त को 12.73 हेक्टेयर कमांद क्षेत्र और अपर एवं लोअर बेहना के 10.97 हेक्टेयर कमांद क्षेत्र को 4 सितंबर, 2024 को पूरा किया गया और इन्हें चलाने, एवं रख-रखाव के लिए संबंधित कृषक विकास संघ को सौंप दिया। इन दोनों उप-परियोजनाओं में विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को जांचने के लिए उप-परियोजना निदेशक (एई), एमपीएच, एसडब्ल्यूसी, पीएमसी विशेषज्ञों और जिला परियोजना प्रबन्धक मण्डी की टीम का संयुक्त दौरा डोहग में आयोजित किया गया। जिला परियोजना प्रबन्धक इकाई, मण्डी के अंतर्गत इस वर्ष रागी के 11 प्रदर्शनी प्लॉट विभिन्न उप-परियोजनाओं में लगाए गए हैं। सितम्बर माह के दौरान 11 में से 4 उप-परियोजनाओं में रागी के खेतों का निरीक्षण भी किया गया तथा किसानों को मोटे अनाजों (श्रीअन्न) की पौष्टिकता और उसके उपयोग की जानकारी भी दी गई, ताकि किसान इसे ज्यादा से ज्यादा उपजाकर अपनी थाली में जगह दे सकें और तंदरूस्त रहें।

शिटाके मशरूम की खेती से किसान होंगे मालामाल

212 किसानों को दिया शिटाके मशरूम उगाने का प्रशिक्षण

हमीरपुर। कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जा रही सरकार की महत्वांक्षी परियोजना, हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (जाइका समर्थित) के माध्यम से पालमपुर में याटस कॉरपोरेशन, जापान, के सहयोग से शिटाके मशरूम खेती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया हैं, जिसमें अब तक 3.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के दूसरे चरण में इस केंद्र के लिए 5.9 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। इस केंद्र में निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जाती हैं।

इस केंद्र में विशेष रूप से शिटाके मशरूम ब्लॉक का उत्पादन किया जाता है, अब तक इस केंद्र ने लगभग 10 हजार ब्लॉकों का उत्पादन किया है, यहां से आम किसान 200 रुपये के हिसाब से ब्लॉक खरीद सकता है जिसमें से लगभग 800 ग्राम शिटाके मशरूम का उत्पादन होता है। अब तक इस केंद्र में जिला किसानों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही, 199 किसानों को 2 दिनों के शिटाके मशरूम कटाई के बाद प्रसंस्करण और रख-रखाव पर 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब तक इस केंद्र द्वारा किसानों को 2675 परीक्षण ब्लॉक वितरित किये गए हैं । पूरे सूखे, गुच्छे और पाउडर के रूप में लगभग 53 किलोग्राम तथा लगभग 65 किलोग्राम ताजा शीटाके मशरूम और 1205 तैयार ब्लॉक स्थानीय स्तर पर बेचकर कुल 3.31 लाख का राजस्व अर्जित किया है।

इस मशरूम का वैज्ञानिक नाम लेंटिनुला एडोड्स है जिसे आम भाषा में शिटाके मशरूम बोला जाता है यह अपने विशेष पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ सुगंध और स्वाद में भी अद्वितीय है इसी वजह से इसे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। शिटाके मशरूम में प्राकृतिक रूप से मौजूद लेंटीनन नामक बायो एक्टिव कंपाउंड, एंटी-ट्यूमर और कैंसर-रोधीगुणों के लिए जाना जाता है। यह शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसके अलावा, यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हुए शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने में शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है। शिटाके मशरूम के अन्य स्वास्थ्य लाभों में वजन घटाने में सहायता करना और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना शामिल है। यह मशरूम त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है, जिससे त्वचा हमेशा जवान और ग्लोइंग बनी रहती है। हमारे किसान समूहों ने इसे विभिन्न रूपों में तैयार किया है जैसे ताजे मशरूम, सुखाए हुए मशरूम, फ्लेक्स और पाउडर, ताकि इसे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार या विभिन्न व्यंजनों में इनका इस्तेमाल कर सके। व्यंजनों में मुख्य रूप से

शिटाके मशरूम सूप, शिटाके मशरूम बिरयानी, शिटाके मशरूम करी, शिटाके मशरूम पकोड़े, सूखे हुये शिटाके का सूप आदि व्यंजन तैयार किये जाते हैं। उपरोक्त गुणों को और हमारे आजकल की जीवन शैली को देखते हुए अगर हम शिटाके मशरूम को अपनी दैनिक थाली में जगह दें तो स्वाद के साथ साथ हम

कांगड़ा के विभिन्न उप परियोजनाओं के किसानों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें मुख्यतय बैजनाथ, सागर, परौर, रिदुआं कुहल, पालमपुर-1, पालमपुर-2, नयी कुहल और भट्टू क्षेत्रों के किसान थे। इस केंद्र में अब तक 16 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिनमें शिटाके मशरूम की खेती पर 6 दिनों के 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं और 212 किसानों ने भाग लिया। साथ ही, 199 किसानों को 2 दिनों के शिटाके मशरूम कटाई के बाद प्रसंस्करण और रख-रखाव पर 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब तक इस केंद्र द्वारा किसानों को 2675 परीक्षण ब्लॉक वितरित किये गए हैं । पूरे सूखे, गुच्छे और पाउडर के रूप में लगभग 53 किलोग्राम तथा लगभग 65 किलोग्राम ताजा शीटाके मशरूम और 1205 तैयार ब्लॉक स्थानीय स्तर पर बेचकर कुल 3.31 लाख का राजस्व अर्जित किया है।

इस मशरूम का वैज्ञानिक नाम लेंटिनुला एडोड्स है जिसे आम भाषा में शिटाके मशरूम बोला जाता है यह अपने विशेष पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ सुगंध और स्वाद में भी अद्वितीय है इसी वजह से इसे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। शिटाके मशरूम में प्राकृतिक रूप से मौजूद लेंटीनन नामक बायो एक्टिव कंपाउंड, एंटी-ट्यूमर और कैंसर-रोधीगुणों के लिए जाना जाता है। यह शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसके अलावा, यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हुए शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने में सक्षम रखता है। दिल की बीमारियों से बचाव के लिए भी यह मशरूम काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होता है। विटामिन-डी का एक उत्कृष्ट स्त्रोत होने के कारण हड्डियों की मजबूती व इनका स्वास्थ्य बनाए रखने के साथ-साथ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों से बचाव में मदद करता है, क्योंकि यह शिटाके मशरूम सूप, शिटाके मशरूम बिरयानी, शिटाके मशरूम करी, शिटाके मशरूम पकोड़े, सूखे हुये शिटाके का सूप आदि व्यंजन तैयार किये जाते हैं। उपरोक्त गुणों को और हमारे आजकल की जीवन शैली को देखते हुए अगर हम शिटाके मशरूम को अपनी दैनिक थाली में जगह दें तो स्वाद के साथ साथ हम अपने बच्चों और अपने बजुर्गों की सेहत का ख्याल रख पाएंगे। हमारे किसान समूह द्वारा इन सभी गुणकारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिटाके मशरूम के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करते हैं। इन उत्पादों को खरीदने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित किसान समूहों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

पालमपुर के अंतर्गत 18 सिंचाई योजनाएं निर्माण स्तर पर

हमीरपुर। जायका परियोजना जिला पालमपुर के पांच खण्ड क्षेत्रों में सितंबर में 18 सिंचाई योजनाएं निर्माण कार्य के स्तर पर आ गई हैं, जबकि चंबा खंड की रूपियाना में एक सिंचाई योजना कृषक विकास संघ को सौंपी जा चुकी है।

इसी परियोजना जिला में 139 प्रशिक्षण आयोजित किए जाएगा। इसके अलावा, आठ अन्य योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। खण्ड परियोजना प्रबन्धक, चंबा के अंतर्गत रूपियाना में एक प्रवाह सिंचाई योजना को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। इसका कमांद क्षेत्र 6.75 हेक्टेयर, इसकी लागत लगभग 17.89 लाख है, 18 सितंबर 2024 को संबंधित कृषक विकास संघ को सौंप दी है।

गए, जिनमें कुल 5012 किसानों ने भाग लिया। परियोजना जिला पालमपुर में पांच खंड प्रबन्धक इकाइयां-चम्बा, ज्वाली, धर्मशाला, देहरा और पालमपुर आती हैं। अभी तक कुल 10 सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य ठेकेदारों को सौंपे गए हैं और जल्दी ही वहां कार्य भी शुरू हो इस उप-परियोजना में अब विस्तार गतिविधियों को लागू किया जा रहा है। जायका परियोजना की पांचों खण्ड इकाइयों में हुए 139 जागरूकता शिविरों में फार्म प्रबंधन और बुक कीपिंग, अभिविन्यास और आवश्यकता मूल्यांकन, उद्देश्य और मानदंड, बुनियादी इंजीनियरिंग कौशल, सिंचाई और जल प्रबंधन, प्रबंधन समिति के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर जानकारी ही गई। इन सभी 5012 किसानों को इन प्रशिक्षणों के माध्यम से गोभी, मटर, मूली और अन्य सर्दियों के मौसम की सब्जियों के बीज किट वितरित किए गए। हिमाचल प्रदेश में परियोजना द्वारा बनाई जा रही सभी उप-परियोजनाओं में किसानों के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है ताकि किसान अपनी उप-परियोजना में चल रही सभी योजनाओं की जानकारी अपनी स्थानीय बोली के माध्यम से ले सके और उप परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करते हुये धान, मक्की और गेहूं से हटकर वह सब्जियों के उत्पादन करना शुरू करे। इसी सन्दर्भ में चबुआं और कियोर घारियां में दो नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। खण्ड परियोजना प्रबन्धन क्षेत्र, चंबा में दो उप-परियोजनाओं, एफआईएस कोलका प्रियंगल और एफआईएस गुलेल के लिए और 9 सितंबर को एफआईएस पुलेवाली (बीपीएमयू देहरा), एफआईएस धोंडू और एफआईएस नन्हिया (बीपीएमयू धर्मशाला) और एफआईएस छू नाला (बीपीएमयू पालमपुर) में निर्माण और विस्तार गतिविधियों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त क्षेत्र का दौरा किया गया।

उप परियोजना निदेशक (एसडब्ल्यूसी), परियोजना प्रबंधन सलाहकार सेवा के विशेषज्ञ और जिला परियोजना प्रबन्धक इकाई, पालमपुर की एक टीम ने 23 से 25 सितंबर 2024 तक खण्ड परियोजना प्रबन्धक, चंबा के तहत प्रवाह सिंचाई योजना रूपियाना, सरुल, संघनी और जुंगरा शावा का दौरा किया। टीम ने चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और कृषक विकास संघ और परियोजना लाभार्थियों के साथ बातचीत की। टीम ने किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा की। आधारभूत सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अब कुल सर्वेक्षणों की संख्या 64 उप-परियोजनाओं तक पहुंच गई है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, परियोजना प्रबंधन सलाहकार के विशेषज्ञों और जिला परियोजना प्रबन्धक इकाई, पालमपुर के उप-परियोजना निदेशकों द्वारा 7

''फसल विविधीकरण से कृषि उपज को बढ़ाना है, कृषि के क्षेत्र में प्रदेश का नाम और ऊंचा उठाना है''

राजेश्वर ठाकुर
मीडिया सलाहकार

एक और प्रयास

आज के तकनीकी युग में, हम अपने किसान भाइयों को विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों से अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में, हमने 'फार्म फॉरवर्ड' नामक मासिक हिंदी ई-पत्रिका का शुभारंभ किया है। यह ई-पत्रिका किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत बनेगा, जिसमें परियोजना की गतिविधियों, उपलब्ध योजनाओं, कार्यशालाओं और सफलताओं की जानकारी मिलेगी। हमारा ऊद्देश्य है कि किसान अपने घर से ही आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकें। हम आपके अनुरोध करते हैं कि इस ई-पत्रिका से सक्रिय रूप से जुड़ें और अपने सुझाव और सफलता की कहानियाँ साझा करें। मिलकर हम कृषि क्षेत्र में नवाचार और जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। वलिए, एक साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे कृषि समुदाय के लिए एक सफल भविष्य का निर्माण करते हैं।

धन्यवाद!

बेहरन झरेड़ी में किसानों के लिए हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम; कुल्लू की शेगलु सिंचाई योजना का लिया निरीक्षण

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 की खण्ड परियोजन प्रबंधन इकाई बिलासपुर की ओर से सूक्ष्म सिंचाई योजना बेहरन झरेड़ी में किसानों के लिए फार्म प्रबंधन और बहीखाता पद्धति पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कि 42 किसानों ने इस शिविर में भाग लिया।

इस दौरान केवीए के उप प्रधान बुद्धि सिंह व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर किसानों को पालक और धनिया के बीज भी बांटे गए। परियोजना की ओर से एग्रीकल्चर ऑफिसर कौशिक ठाकुर व मोहित नायक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ने किसानों को

सूक्ष्म सिंचाई योजना बेहरन झरेड़ी के प्रशिक्षण शिविर में फार्म प्रबंधन और बहीखाता पद्धति बारे जानकारी दी।

केवीए के उप प्रधान बुद्धि सिंह ने बताया कि परियोजना की ओर से ऐसे जागरुकता शिविर लगने चाहिए जिससे कि किसानों को समय-समय पर विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे ताकि किसान परियोजना की योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

कुल्लू। बीपीएमयू कुल्लू में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के तहत रुपए 85.79 लाख से बन रही प्रवाह सिंचाई उप परियोजना शेगलु का निरिक्षण मोहन सिंह (कनिष्ठ अभियंता) तथा साइट सुपरवाइजर अश्वनी कुमार ने

किया। उन्होंने कहा कि यह उप परियोजना 12 मार्च, 2024 से शुरू हुई थी और मार्च, 2025 के समयावधि से पहले इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रवाह सिंचाई उप परियोजना शेगलु का एक्सटेंशन इन्चार्ज डॉ. हेम लता को बनाया गया है और इनकी देख-रेख में ही कृषि विस्तार का सारा कार्य किया जा रहा है।

का लगभग 30-35 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर लिया है। इस उप परियोजना के तैयार होने के बाद लगभग 360 बीघा भूमि को सिंचित होगी और जिसमें 189 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इस उप परियोजना के निर्माण के साथ-साथ किसानों को सब्जी उत्पादन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके जागरुक किया जा रहा है। प्रवाह सिंचाई उप परियोजना शेगलु का एक्सटेंशन इन्चार्ज डॉ. हेम लता को बनाया गया है और इनकी देख-रेख में ही कृषि विस्तार का सारा कार्य किया जा रहा है।

बलजीत सिंह सन्धू
वरिष्ठ सलाहकार

हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपनी योजनाओं को ला रही है ताकि किसानों का जीवन सुलभमय और खुशहाल हो।

प्रदेश सरकार के इसी प्रयास और दूरदर्शिता को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 (जायका-ओडीए) के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं व सिंचाई उप-परियोजनाओं को विभिन्न संचार माध्यमों से किसानों तक पहुँचा रही है।

कार्यक्रमों के इस विस्तार और प्रचार के लिए परियोजना का सूचना संचार अनुभाग विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर रहा है ताकि इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले किसानों तक परियोजना की पूरी जानकारी पहुँच सके, इसी कड़ी में यह अनुभाग किसानी ई-पत्रिका का प्रकाशन करने जा रहा है।

मैं सभी किसानों भाइयों की ओर से ई-पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए परियोजना प्रबंधन को शुभकामनायें देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित

सिंचाई योजना छू नाला में किसानों को दी सिखलाई

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के पालमपुर बीपीएमयू के अंतर्गत आने वाली उप-परियोजना छू नाला में किसानों के लिए बेसिक इंजीनियरिंग स्किल्स पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस शिविर में खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर द्वारा किसानों को फसलों की खेती में भूमि समतलन और जल निकासी प्रणाली के बारे में जागरूक किया गया व विभिन्न फसलों की खेती में मशीनीकरण के महत्व बारे जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान जल वितरण के लिए प्रवाह सिंचाई प्रणाली के निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों (स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली) पर भी किसानों को अवगत करवाया गया।

स्वाति सूद, कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान किसानों को फसलों की खेती में भूमि समतलन और जल निकासी प्रणाली के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सही ढंग से किए गए भूमि समतलन से सिंचाई में पानी का समान वितरण होता है और जलभराव की समस्या से बचा जा सकता है।

उन्होंने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जो जल प्रबंधन में अत्यधिक प्रभावी हैं। वहीं, विक्रांत राणा, कृषि विशेषज्ञ ने कहा कि इस कार्यक्रम में किसानों को खेती में मशीनीकरण के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग न केवल श्रम को कम करता है, बल्कि फसल उत्पादन को भी बढ़ाता है। खेती में विभिन्न कृषि उपकरणों का प्रयोग करने से किसानों का श्रम कम होता है और उन्हें अधिक उत्पादकता मिलती है।

उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण सत्र किसानों को नई तकनीकों के साथ सशक्त करने और कृषि की दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

छू नाला योजना से 32.45 है. जमीन होगी सिंचित

उप-परियोजना छू नाला से सगूर और चाबान गांवों के किसानों की 32.45 हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे फसलों को बेहतर पानी उपलब्ध होगा और पैदावार में वृद्धि होगी।

कृषक विकास संघ (केवीए) इस परियोजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगा। यह संघ 88 किसानों की मदद करेगा और एफआईएस के 100 घंटे के परीक्षण के बाद योजना को सुचारू रूप से चलाएगा।

डॉ. अमित भूषण, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, पालमपुर।

चंबा की सिंचाई योजना दुल्ला में किसानों को किया जागरुक

चम्बा। फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत बहाव सिंचाई योजना दुल्ला में सब्जी का प्रदर्शन प्लॉट लगाया है ताकि इस प्रदर्शन प्लॉट को देखकर और किसान भी इससे प्रेरित हो सकें और उनका झुकाव परम्परागत खेती से हटकर सब्जियों का उत्पादन करने में लगे। बहाव सिंचाई योजना दुल्ला पूरी होने पर लगभग 112 बीघा कृषि भूमि को सिंचित किया जाएगा। इस उप-परियोजना के अंतर्गत 59 परिवार लाभान्वित होंगे। इस प्रदर्शनी के लिए किसानों द्वारा मूली की फसल को चुना गया। इसमें खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई चंबा के डॉ. बाबर अली (कृषि विकास अधिकारी), साहिल पठानिया (कृषि विस्तार अधिकारी), राधिका कपूर (कृषि अधिकारी) ने मूली की फसल से संबंधित किसानों को पूरी जानकारी दी और उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मूली की फसल की मार्केटिंग के लिए उन्हें एपीएमसी बालु जिला चम्बा उपयुक्त स्थान रहेगा। जो कि इस गांव से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

जहां पर वह सुगमता से अपने खेतों में उगाई गई मूली की फसल को बेच सकेंगे। इसके बाद उन्होंने अन्य किसानों के खेतों का दौरा किया जहां पर करीब 1 महीने पहले रागी/ कोदरा और सब्जी का प्रदर्शन प्लॉट लगाए गए थे।

लाहौल में भी सिंचाई योजना हो रही लागू

हमीरपुर। 10 सितंबर, 2024 को, बीपीएमयू कुल्लू के तहत यार्टी (टिन्नू) उप-परियोजना में सिंचाई और जल प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई, जहां किसानों को बेहतर सिंचाई तकनीकों से परिचित कराया गया। कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को जल प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांतों और प्रथाओं

से अवगत कराना था। इस परियोजना से कुल 35 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, विशेष रूप से वे किसान जिनके पास सिंचाई के सीमित संसाधन हैं। कृषक विकास संघ के अध्यक्ष तेंजिन नाम्ग्याल के नेतृत्व में यह परियोजना सफलतापूर्वक प्रगति कर रही है। यह परियोजना 25.71 हेक्टेयर की सिंचाई योग्य भूमि को कवर करती है। अब तक हेड वियर का और क्रेट कार्य पूरा हो चुका है, 80 प्रतिशत जीआई मुख्य पाइपलाइन का काम भी पूरा हो गया है, और 8 में से 5 संग्रहण टैंक तैयार हो चुके हैं। परियोजना की कुल लागत 61.995 लाख है, जिसमें से 58.68 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। भविष्य में, यह परियोजना न केवल खेती को सुगम बनाएगी बल्कि पानी की बर्बादी को भी रोकने में मदद करेगी, जिससे 35 कृषक लाभान्वित होंगे।

जायका कृषि परियोजना-2 में भी प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा : डॉ. चौहान

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती से जुड़ी नीति के तहत हि.प्र. फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना क्षेत्र में भी इसका विस्तार करने का आह्वान परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने किया। हाल ही में विभिन्न फसल विविधीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों में डॉ. चौहान इस बात पर जोर दे रहे हैं ताकि जहां किसानों के खेतों की उपजाऊ क्षमता को पुनर्जीवित किया जा सके और कृषि रसायनों से मुक्त कृषि उत्पादन उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

डॉ. चौहान ने किसानों को बताया कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक खेती से उपजी गेहुं व मक्की का समर्थन मुल्य भी घोषित कर दिया है जो कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

इसी बीच सिरमौर जिला के पांवटा-साहिब के एक गांव में प्राकृतिक खेती का किसानों ने लाभ उठाया। आसपास के किसानों को यह देख कर हैरानी

आंधी-तूफान से पांवटा साहिब के आस-पास के गांवों में ढह गई फसल। इसके बावजूद टाईं और सिरमौर के भगाणी फार्म में प्राकृतिक खेती से खड़ी हुई फसल

हुई कि प्राकृतिक खेती से तैयार फसल भारी बारिश के बावजूद खेतों में खड़ी रही, जबकि अन्य जगहों पर फसलें ढह गईं थी। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में तेज बारिश व आंधी-तूफान से पांवटा-साहिब के कुछ गांवों में मक्की, धान, गन्ना सहित चारे को भी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच ऐसी जानकारी भी मिली है कि कृषि विभाग सिरमौर के भगाणी में स्थापित बीज उत्पादन एवं प्राकृतिक खेती मॉडल फार्म में उगी फसलों का बारिश, आंधी-तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सके। उल्लेखनीय है कि यह फार्म 13 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिसमें से 11 हेक्टेयर पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। इस फार्म में उगाए गए धान, गन्ना व दालों समेत चारे और फूट ट्री को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बड़ी बात ये है कि इस फार्म के साथ और आसपास के क्षेत्रों में उगी किसानों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 (जायका ओडीए) के स्वामित्व में डॉ. सुनील चौहान, परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना भवन, कृषि परिसर, हमीरपुर-177001 से संपादित, प्रकाशित एवं मुद्रित।
प्रधान संपादक: डॉ. सुनील चौहान, परियोजना निदेशक। सलाहकार संपादक: राजेश्वर ठाकुर। फोन: 01972-223059. ई-मेल : iechpjicaagriculture9@gmail.com
संपादक: डॉ. जगदीश जंजीहा, विषय-विशेषज्ञ (सूचना-शिक्षा-संचार)। सम्पादकीय सहयोग: ज्योति ठाकुर, शालभ ठाकुर और अंकुश पटियाल। सूचना-शिक्षा-संचार परामर्श: सुशील कुमार शर्मा।